फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 180 प्रभात जयपुर, रविवार 1 फरवरी, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

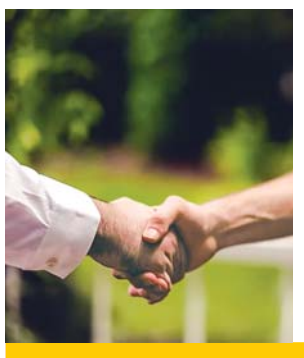

How To Acquire Neighbours

There were no compound walls; the back doors of the houses remained open all day long. It was quite common for members of the families to drop in unannounced

Ancient Pregnancy Test

Ancient Greek Gold Earrings

अचानक क्यों बदला-बदली हो गई, जयपुर के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में?

कुछ समय पहले तक प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा व प्रभारी रंधावा, पुष्पेन्द्र भारद्वाज को जिलाध्यक्ष बनाने में जुटे हुए थे, पर, फिर, अचानक सुनील शर्मा को जिलाध्यक्ष का पद मिल गया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। यह, राजस्थान के एक मेहनती युवा नेता की राज्य नेतृत्व के हाथों किस तरह राजनीतिक हत्या हुई, इसकी केस स्टडी है।

यह नेता है पुष्पेन्द्र भारद्वाज, जो जयपुर ज़िले के अध्यक्ष बनने की आकांक्षा रखता था। लेकिन आख़िरी समय में उसी नेतृत्व ने उसके साथ विश्वासघात किया, जिसने उससे बड़े-बड़े वादे किए थे, पद का भरोसा दिया था, उसकी इस पद को पाने की तीव्र इच्छा का पूरा फ़ायदा उठाया, लेकिन अंतिम क्षणों में उसे धोखा दे दिया, तथा अधिक "कीमत" देने वाले ऐसे नेता को पद दे दिया, जो राज्य नेतृत्व के लिए अधिक लाभकारी साबित हो सकता था।

- **क्या सुनील शर्मा ने ज्यादा ऊंची बोली लगा दी थी, यह पद पाने के लिए?**
- **कुछ ऐसा ही अजीब सा हाल है, राजसमंद के जिलाध्यक्ष की नियुक्ति का मामला। पूर्व विधानसभाध्यक्ष सी.पी. जोशी अपने खास समर्थक आदित्य प्रताप सिंह को जिलाध्यक्ष बनवाना चाहते हैं और उनसे वादा भी कर चुके हैं। पर, दोनों पड़ोसी जिलों, प्रतापगढ़ व चित्तौड़ में भी दो राजपूत जिलाध्यक्ष हैं। अतः, राजसमंद में भी एक राजपूत को जिलाध्यक्ष बनाना, शायद राजनीति की दृष्टि से संभव नहीं लगता?**
- **पर, सी.पी. जोशी अड़े हुए हैं तथा डोटासरा आजकल सी.पी. जोशी के साथ हैं।**
- **"बड़े" नेताओं के वर्तमान समीकरण जानना जरूरी होता है।**

सूत्रों का कहना है कि डोटासरा और रंधावा, दोनों ही भारद्वाज का समर्थन कर रहे थे और उन्होंने उसे आश्वस्त किया था कि जिलाध्यक्ष पद उसी को मिलेगा। यह भी बताया जाता है कि उसने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने से लेकर बड़े-बड़े काफ़िलों की व्यवस्था तक, सब कुछ किया, यहाँ तक कि फंड्स और कथित तौर पर एक भूखंड की व्यवस्था करने तक की चर्चाएं भी रहीं।

लेकिन आख़िरी समय में, जब जयपुर के ज़िला अध्यक्ष की घोषणा हुई, तो यह पद सुनील शर्मा को दे दिया गया, एक विवादास्पद व्यक्ति, जिन्हें पिछली बार टिकट नहीं मिला था, जब शशि थरूर ने उनके ख़िलाफ़ ट्वीट किया था, और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गांधी परिवार के ख़िलाफ़ कुछ असंसदीय टिप्पणियाँ की थीं। सुनील शर्मा एक प्रमुख कांग्रेसी परिवार से आते हैं और एक धनी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं।

कांग्रेस पार्टी में "खेल" के टूटने-बिखरने और कैसे सबसे पुख़्ता आश्वासित सपने चकनाचूर हो जाते हैं, की पूरी संरचना है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा देश में 50 जगह बजट का प्रचार - प्रसार करेगी

नयी दिल्ली, 31 जनवरी । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बार के केन्द्रीय बजट का प्रचार-प्रसार करने के लिए देशभर में 50 जगहों पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करेगी। साथ ही, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, और अखबारों में संपादकीय लिख कर भी लोगों को बजट के फायदे बताएगी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भाजपा केन्द्रीय बजट को लेकर एक फरवरी से 15 फरवरी तक देश भर अभियान चलाएगी और लोगों को बजट के बारे में जानकारी देगी।

- **संवाददाता सम्मेलन, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया व अखबारों में सम्पादकीय के जरिये बजट के फायदे बताये जायेंगे।**

इसके लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ के नेतृत्व में एक केंद्रीय समिति का गठन किया है, जिसमें सरोज पांडेय, सर्वअनिल एंटनी, नरेंद्र सिंह रैना, जीवीएल नरसिम्हा राव, देवेश कुमार, श्रीकांत शर्मा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, संजय टंडन और गुरु प्रकाश पासवान सहित कई अन्य नेता शामिल हैं।

पहली बार जनप्रियता नहीं आर्थिक परिस्थितियां डिक्टेट करेंगी नए बजट को

नए बजट की सबसे बड़ी चुनौती निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल करने की है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट, कल्याणकारी योजनाओं वाला राजनीतिक दस्तावेज़ कम और बाज़ार के हिसाब से तैयार किया गया आर्थिक बयान ज्यादा लग रहा है। यह बदलते और चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में विकास को स्थिर रखने की सरकार की जल्दबाज़ी को दर्शाता है।

अमेरिका के नेतृत्व में बढ़ते व्यापार और टैरिफ टकराव, विदेशी पूंजी के प्रवाह में कमज़ोरी और निजी निवेश में साफ़ दिखाई दे रही सुस्ती का सामना करते हुए, सरकार आर्थिक सुधारों, खासतौर पर टैक्स और पूंजी बाज़ार सुधारों को अपनी वित्तीय रणनीति के केन्द्र में रखने के लिए तैयार दिख रही है।

बजट 2026 की सबसे बड़ी चुनौती निवेशकों का भरोसा दोबारा हासिल करना है। पिछले एक साल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की रफ्तार धीमी पड़ी है, जबकि बार-बार नीतिगत आश्वासनों के बावजूद, घरेलू निजी पूंजी खर्च सतर्क बना हुआ है।

- **गत वर्ष से विदेशी निवेश की रफ्तार धीमी पड़ी है। नीति निर्माता बजट में ऐसे संकेत देने का प्रयास करेंगे, जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों में जोखिम लेने की इच्छा पुनः पैदा हो जाए।**
- **बाज़ार के जानकारों ने उम्मीद जताई कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्सेशन पर साहसिक उपायों की घोषणा करेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को काफी हद तक सरल बनाया जा सकता है।**
- **सरकार सिक्युरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स भी वापस ले सकती है, जिसके लिए निवेशक लम्बे समय से मांग कर रहे हैं।**

अब नीति-निर्माताओं को लगता है कि सिर्फ़ ऊपर से स्थिरता दिखाना काफ़ी नहीं है। घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के निवेशकों में जोखिम लेने की इच्छा लौटाने के लिए कर व्यवस्था और बाज़ार नियमों में ढांचागत संकेत देना ज़रूरी है।

बाज़ार के जानकारों को उम्मीद है कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्सेशन पर साहसिक उपायों की घोषणा करेगी। यह उम्मीद बढ़ रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को काफ़ी हद तक सरल और तर्कसंगत बनाया जा सकता है, ताकि लंबे समय के निवेश को ज़्यादा आकर्षक बनाया जा सके।

उतना ही अहम कदम सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (एस.टी.टी.) को वापस लेने या पूरी तरह हटाने का होगा। निवेशक लंबे समय से इसकी मांग करते रहे हैं और उनका तर्क है कि यह टैक्स तेज़ी से होने वाले लेन-देन को हतोत्साहित करता है और भारत को अन्य उभरते वित्तीय बाज़ारों के मुक़ाबले कम प्रतिस्पर्धी बनाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या एनसीपी के नए समीकरणों में शरद पवार की पूछ नहीं हुई

सुनेत्रा पवार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के मुद्दे पर शरद पवार ने कहा, मुझे तो इस बारे में मीडिया से जानकारी मिली

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बुधवार सुबह एक विमान दुर्घटना में हुए निधन के बाद, उनकी पत्नी सुनेत्रा उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उनकी बड़ी भूमिका संभालने जा रही हैं। अजित पवार के चाचा और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा कि यह निर्णय एनसीपी ने लिया है तथा इस विषय में पवार परिवार से कोई परामर्श नहीं किया गया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या अजित पवार के उत्तराधिकारी को तय करने की प्रक्रिया से उन्हें अलग रखा गया, तो शरद पवार ने कहा, "मुझे नहीं पता।"

- **ज्ञातव्य है कि सुनेत्रा पवार ने शनिवार शाम महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की, इस कार्यक्रम में शरद पवार ने शिरकत नहीं की।**
- **इस बीच एनसीपी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों को एक करना चाहते थे, वे शरद पवार के जन्मदिन, 12 दिसम्बर को ही उन्हें एकता का तोहफा देना चाहते थे, पर, ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन अजित पवार ने विलय की कोशिशें नहीं छोड़ीं।**

वरिष्ठ पवार की टिप्पणी साफ़ तौर पर राजनीति और परिवार के बीच की सीमा रेखा को दर्शाती है। ज्ञातव्य है कि जुलाई 2023 में, एनसीपी दो गुटों में बँट गई थी, जब अजित पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ते हुए, पार्टी से अलग होकर राज्य की राजनीति में अपनी अलग राह बनाई थी।

शरद पवार ने इस घटनाक्रम से खुद को अलग रखते हुए कहा कि उन्हें शनिवार शाम प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह के बारे में मीडिया के ज़रिये जानकारी मिली।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ने सुनेत्रा पवार को बधाई दी

नयी दिल्ली 31 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा ,"महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनने और इस दायित्व को संभालने वाली पहली महिला बनने पर, सुनेत्रा पवार जी को हार्दिक शुभकामनाएँ। मुझे विश्वास है कि वे राज्य के लोगों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजित दादा पवार के विज़न को साकार करेंगी।"

- **उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपमुख्यमंत्री के रुप में दिवंगत अजित पवार के विज़न को साकार करेंगी।**

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता अजित पवार की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका यूएन (संयुक्त राष्ट्र संघ) को आर्थिक तंगी में जकड़कर खत्म करना चाहता है?

अमेरिका, जो अब तक यूएन का सबसे बड़ा दानदाता था, ने 2.2 अरब डॉलर का अपना घोषित योगदान लटका रखा है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है, जिसे उसके महासचिव ने एक आसन्न वित्तीय आपदा बताया है। एक ऐसा संकट, जिसके परिणाम न्यूयॉर्क मुख्यालय से कहीं आगे, दुनिया के सबसे नाज़ुक क्षेत्रों तक जाते हैं। इस आपात स्थिति के केन्द्र में अमेरिका है, जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता है और जिसे वर्तमान में संगठन के नियमित परिचालन बजट के लिए लगभग 2.2 अरब डॉलर और चालू आकलन शुल्क देना है।

- **आर्थिक तंगी केवल बैलेंस शीट का मुद्दा नहीं है, बल्कि, यूएन की विश्वसनीयता का अहम मुद्दा है।**
- **आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने से, यूएन की निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ती है, तथा दान-दाता हावी हो जाते हैं, और फिर उन समृद्ध देशों के एजेंडे के अनुरूप काम करने को मजबूर हो जाएगी, विश्व की यह अति महत्वपूर्ण संस्था।**
- **इस परिवर्तन की सबसे ज्यादा मार प्रगतिशील, थर्ड-वर्ल्ड देशों पर पड़ेगी। जिनके संकट के समय, चाहे वह महामारी का समय हो या शिक्षा का मुद्दा या शरणार्थियों की समस्या, यूएन ही एक मात्र संस्था है, जो बुरे दिनों में काम आती है, क्योंकि इन देशों के पास कोई अन्य विकल्प है ही नहीं।**

हालाँकि संयुक्त राष्ट्र की फंडिंग को लेकर विवाद नए नहीं हैं, लेकिन बकाया राशि का आकार और समय असामान्य रूप से अस्थिरताकारी है। संयुक्त राष्ट्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)